पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 18, अंक 2/2017

किसानों को जैविक खेती की ओर वापस लौटना होगा - प्रभुलाल सैनी

हमारे देश की 1960 से पहले जैविक खेती के मामले में पूरी दुनिया में पहचान थी। इसके बाद हरित क्रांति के दौर में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के मकसद से रासायनिक खेती को बढ़ावा दिया गया। इससे देश में खाद्यान्नों की मात्रा में तो बढ़ोतरी हुई लेकिन उसके दुष्परिणाम आज हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। इन दुष्परिणामों को रोकने के लिए हमें वापस जैविक खेती की ओर लौटना होगा।

उक्त विचार प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, राजस्थान ने 'कट्स' द्वारा राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परियोजना प्रो-ओर्गेनिक-द्वितीय के शुभारम्भ के अवसर पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का विचार सराहनीय है। इसके माध्यम से किसान की आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। किसानों को इसके लिए अनुदान भी दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पश्चिमी भाग के रेगिस्तान वाले क्षेत्र को राज्य सरकार सम्पूर्ण जैविक कृषि क्षेत्र कर सकती है। इस क्षेत्र में अब बाड़मेर तक इंदिरा गांधी नहर का पानी आ चुका है।

कार्यक्रम में विकास सीताराम भाले, आयुक्त, कृषि विभाग ने कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों से उत्पादकता तो बढ़ रही है लेकिन इससे सतत विकास में योगदान नहीं मिल रहा। जैविक खेती को बढ़ाने के लिए किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी जागरूक करना होगा।

इस अवसर पर डॉ. शीतल प्रसाद शर्मा, निदेशक स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ने कृषि उत्पाद के घरेलू प्रमाणिकरण में सुधार करने की आवश्कता जताई। डॉ. हेमा यादव, निदेशक नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ने जैविक उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा दिलाने की जरूरत पर बल दिया। डॉ. कनिका वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय ने कहा कि जैविक खाद्यान्न में पोषक तत्व अधिक होते हैं। इसके लिए किसानों व उपभोक्ताओं को जागरूक करने की जरूरत है।

वागधारा संस्था बांसवाड़ा के पी.एल. पटेल ने बताया कि बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का उपयोग कम हो रहा है। वहां किसान सामुदायिक जैविक खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने देश व विदेश स्तर पर जैविक खेती के आंकड़ों को दर्शाते हुए कई तथ्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से सतत विकास को बढ़ाया जाएगा। दीपक सक्सेना, सहायक निदेशक ने अपने स्वागत सम्बोधन में सतत विकास व लोगों की जीवनशैली को जोड़ते हुए परियोजना का संक्षिप्त परिचय दिया। राजदीप पारीक, परियोजना अधिकारी ने परियोजना की आगामी गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम में जिले के जैविक खेती पर सराहनीय कार्य करने वाले किसान, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के शोध प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि सहित सौ से भी अधिक भागीदारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस अंक में...

- वसूले 28 हजार करोड़ लेकिन खर्च करना भूले 3
- तेज हो बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई-मोदी . 5
- बिजनेस में भ्रष्टाचार हुआ कम 7
- सबसे सस्ती बिजली देगा भड़ला सोलर पार्क ... 8
- महंगा हुआ पानी, नई दरें लागू 9

शहरी विकास के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय की आवश्यकता

जयपुर नगर निगम के महापौर डॉ. अशोक लाहोटी ने कहा कि जयपुर शहर में नौ से ज्यादा एजेन्सिज या विभाग शहर के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें समन्वय की कमी है। बिना विभागीय समन्वय के विकास कार्य गति नहीं पकड़ पाते।

लाहोटी ने यह विचार 10 अप्रेल 2017 को जयपुर में 'कट्स' द्वारा आयोजित मेयर कॉन्फ्रेन्स के उद्घाटन सत्र में व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। शहरी विकास के कार्य में लगी सभी एजेन्सियों को एक छत के नीचे लाना होगा ताकि बेहतर समन्वय के साथ कार्य हो सके।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एम्पॉवर्ड कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी.एस. दवे ने बताया कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी निकायों को बहुत से अधिकार दिए गए हैं। इसमें मुख्य बात वार्ड कमेटियों के गठन की है, लेकिन प्रदेश में अभी तक वार्ड कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। शहरी निकाय इन कमेटियों का गठन कर विकास कार्यों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ा सकते हैं।

जोधपुर के महापौर घनश्याम ओझा ने सुझाव दिया कि नागरिकों की सेवाएं ऑनलाइन तरीके से प्राप्त हो सके इसके लिए कार्य करना होगा। इससे बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी। कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने परियोजना की जानकारी देते हुए कहा कि शहरी सुशासन के लिए सिटी मेयर्स को सशक्त करने की आवश्यकता है।

'कट्स' के परियोजना समन्वयक अमरदीप सिंह ने बताया कि राजस्थान सिटी मेयर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है जो कि जोधपुर के मेयर घनश्याम ओझा की अध्यक्षता में क्रियान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न महापौर एवं निकायों के सभापतियों ने भाग लिया।

बैंक उपभोक्ता अपने अधिकारों को जानें

बैंक उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझें और जागरूक रह कर अपने जमा धन का सकारात्मक ढंग से प्रबंधन करें, तो वह कई तरीकों से लाभान्वित हो सकता है। आधी-अधूरी जानकारी से किए गए बैंकिंग व्यवहार उसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।

जोबनेर स्थित नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के सभा भवन में भारतीय रिजर्व बैंक व 'कट्स' संस्था के सहयोग से आयोजित 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता' कार्यशाला में मुख्य अतिथि लीना जे. शर्मा, सहायक मैनेजर, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय विकास विभाग ने अपने संबोधन में यह सन्देश दिया।

उन्होंने डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के उपयोग की जानकारी, बैंकिंग व्यवहार में सावधानी बरतने, अनावश्यक ऋण जाल में न फंसने की सलाह देते हुए बताया कि अगर बैंक द्वारा गलत जानकारी देकर निवेश कराया जाता है, तो यह संबंधित बैंक की लापरवाही होगी। इसकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल, रिजर्व बैंक को की जा सकती है। कार्यक्रम में दिशा ट्रस्ट के चीफ काउंसलर मुनीष कोठारी व विभिन्न बैंकों के स्थानीय अधिकारियों ने बैंकों में सुरक्षित निवेश व उपायों के बारे में अनेक जानकारियां प्रदान की।

'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने 'कट्स' द्वारा सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से लोगों के बीच चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर खाताधारक को बैंक अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन 'कट्स' की सहयोगी संस्था आत्माराम संस्थान के सचिव आत्माराम ने किया।

रीजेंट खरीद में करोड़ों का घालमेल

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों मे डेंगू, मलेरिया, हीमोग्लोबिन की कमी व अन्य संक्रमणों की जांच में काम आने वाले रीजेंट्स की हर साल बिना निविदा के खरीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरे मामले में करीब 10 करोड़ रुपए सालाना का घालमेल हो रहा है।

मामले के अनुसार राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से 2010 में निविदा के जरिए एक कंपनी की सीबीसी काउंटर '80 प्लस' मशीनें 50 स्थानों पर लगाई गई थी। इसके बाद जांच के लिए आवश्यक रीजेंट्स भी इसी कंपनी से खरीदे जाते रहे।

इस एक सेट की कीमत 31 हजार रुपए है। कंपनी के किट में सीबीसी जांच करीब 70 रुपए प्रति किट है, जबकि इससे अच्छी गुणवत्ता के किट 35 रुपए प्रति टेस्ट के हिसाब से बाजार में उपलब्ध हैं। *(रा.प., 02.04.17)*

नहीं हो रहा निर्भया फंड का इस्तेमाल

दिल दहला देने वाले 2012 के निर्भयाकांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारों ने बड़े जोर-शोर से कई कदमों का ऐलान किया, मगर उनमें से ज्यादातर योजनाएं परवान ही नहीं चढ़ सकीं। इसी तरह का एक कदम था निर्भया फंड, जिसे 2013 में केन्द्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया था।

इस फंड में हर वित्त वर्ष में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ऐसे में अब तक 3000 करोड़ का फंड जुटाया जा चुका है। लेकिन इस फंड में से अभी तक महज 400 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा था कि अभी तक इस फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। *(रा.प., 07.05.17)*

कर्ज बांटने में सरकार असफल

राजस्थान सरकार ने किसानों की मदद के लिए विश्व बैंक से 545 करोड़ रुपए लिए, मगर यह पैसे किसानों तक पहुंच ही नहीं पाए। सरकार ने वर्ष 2008 में किसानों को कर्ज देने के लिए 832 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी। इस योजना के लिए सरकार ने विश्व बैंक से कर्ज के लिए करार किया। विश्व बैंक ने 832 करोड़ रुपए में से 545 करोड़ रुपए जारी भी किए लेकिन वर्ष 2016 तक इसमें से सरकार महज 42 करोड़ रुपए ही किसानों को कर्ज के रूप में बांट पाई। सरकार का कहना है कि देरी कई तरह के नियम और कायदे-कानून की वजह से हुई। अब सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के 48 करोड़ रुपए विश्व बैंक को ब्याज के तौर पर देगी। *(रा.प., 10.04.17)*

वसूले 28 हजार करोड़ लेकिन खर्च करना भूले

सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर लगाकर लोगों से करोड़ों की वसूली की, लेकिन उसे श्रमिक कल्याण पर खर्च करना ही भूल गई। 1996 में सरकार ने बिल्डिंग एंड अण्डर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट पास किया था। इसके तहत सभी राज्यों को अपने यहां श्रमिकों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाना था। सभी प्रकार के निर्माण पर 1 से 2 फीसदी उपकर वसूल कर राज्यों को यह पैसा इस बोर्ड में देना था। सभी राज्यों ने अपने यहां इस बोर्ड की स्थापना कर दी। देशभर में 2.13 करोड़ श्रमिकों को इसमें रजिस्टर्ड किया गया।

अक्टूबर 2016 तक कुल 28 हजार 455 करोड़ रुपए उपकर के रूप में वसूल कर बोर्ड में दिए गए। लेकिन इसमें से महज 21 फीसदी यानी 6097 करोड़ रुपए ही श्रमिकों के कल्याण पर खर्च किए गए। शेष 22 हजार 358 करोड़ रुपए अभी भी बोर्ड के पास पड़े हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैग को जांच का आदेश दिया है। *(रा.प., 14.06.17)*

घटे नौकरियों के अवसर

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कराए गए सर्वे से यह सामने आया है कि जॉब मार्केट 2013 के बाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है।

देश के छह बड़े शहरों (बेंगलुरु, चैन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली) में कराए गए सर्वे में शामिल 39.2 फीसदी लोगों ने बताया कि वर्तमान में जॉब मार्केट की स्थिति पिछले चार साल में सबसे खराब है। मार्च के मुकाबले मई में स्थिति ज्यादा बिगड़ी है।

मार्च में 32.5 फीसदी लोगों ने जॉब मार्केट की स्थिति को खराब बताया था, यह मई में बढ़कर 39.5 फीसदी हो गई। हालांकि सर्वे में शामिल 32 फीसदी लोग अभी भी आशावान है कि अगले एक साल में जॉब के अवसर पैदा होंगे और स्थिति अच्छी होगी। *(रा.प., 09.06.17)*

अफसरों की ढिलाई से रेंगते रहे वादे

राज्य सरकार बजट में बड़े-बड़े वादे कर जनता को उम्मीद बंधा देती है, लेकिन अफसरशाही की ढिलाई के चलते कई घोषणाएं सालों तक पूरी नहीं होती। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है।

प्रदेश के बजट 2015-16 का रिव्यू किया गया तो यह स्थिति सामने आई। जो घोषणाएं उसी वित्त वर्ष में पूरी होनी थी, उसके काम उस वर्ष में शुरू ही नहीं हुए। इनमें ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन, शिक्षा, मेडिकल हेल्थ व मेडिकल शिक्षा से जुड़ी घोषणाएं शामिल हैं। *(दै.भा., 02.04.17)*

पंच-सरपंचों की जांच अधूरी

गांव की सरकार चलाने वाले पंच-सरपंचों के खिलाफ साढ़े नौ हजार से भी अधिक शिकायतों की जांच अभी ठंडे बस्ते में बंद हैं। इनमें सबसे अधिक मामले जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के हैं। इनमें आपराधिक प्रकरणों जैसे गलत तरीके से चुनाव लड़ने, फर्जीवाड़ा करने और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें हैं।

पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों के अनुसार पंच-सरपंचों के खिलाफ सबसे अधिक आरोप पद का दुरुपयोग करने व वित्तीय अनियमितता बरतने से संबंधित हैं। *(दै.भा., 27.06.17)*

गैराज सें ही नहीं निकली मोबाइल वैन

सरकारी योजना में खरीदी गई गाड़ी सिर्फ 10 हजार रुपए के लिए 10 साल से डीलर के गैराज में खड़ी-खड़ी खराब हो गई। जिस योजना के लिए खरीदी गई अब वह भी बंद हो गई। लेकिन अफसरों के माथे पर शिकन तक नहीं आई।

मामले के अनुसार उद्योग आयुक्त कार्यालय ने स्पेशल स्कीम के तहत केन्द्र के फंड से बाट-माप की मोबाइल वैन का चैसिस 2007 में 98 प्रतिशत राशि का डीडी देकर 4.97 लाख में मैसर्स हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स से खरीदा। लेकिन 10 साल से डीलर के गैराज से लाया ही नहीं गया।

अब डीलर सरकार से 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से करीब 18 लाख रुपए गैराज किराया मांग रहा है। पांच साल पहले विभाग को होश आया और डीलर से बिल मांगा तो डीलर ने चैसिस की दो फीसदी बकाया रकम और गैराज का किराया मांगा तो अफसरों के हाथ-पैर फूल गए। अब मामले की फाइल को फिर से दबा दिया गया है। *(दै.भा., 31.05.17)*

मनरेगा में साढ़े छह लाख काम अधूरे

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) सिर्फ करोड़ों रुपए की स्वीकृतियां जारी करने की गारंटी दे रही है। हाल यह है कि न रोजगार की गारंटी है और न ही स्वीकृत काम पूरा करने की। प्रदेश में साढ़े छह लाख काम बरसों से अधूरे पड़े हैं। अधिकारी हर साल उन्हें प्रगतिरत बताकर फाइलें दौड़ा रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ कागजी कार्यवाही बनकर रह जाते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मनरेगा पर सबसे ज्यादा फोकस होने के बावजूद वहां सबसे ज्यादा काम अधूरे पड़े हैं।

(रा.प., 05.06.17)

असफल रही गरीब कल्याण योजना

कालेधन को लेकर बनाई गई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरी तरह असफल रही है। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कालेधन का खुलासा करने वाली यह योजना फ्लॉप साबित हुई है। राजस्व विभाग के अनुसार योजना में करीब 5 हजार करोड़ रुपए का ही खुलासा हुआ है।

योजना की घोषणा होने से पहले ही कई लोगों द्वारा अपनी नकदी विभिन्न खातों में जमा करना इसकी वजह माना जा रहा है। दूसरा कारण योजना के तहत कर की दर और जुर्माना था। *(रा.प., 02.06.17)*

मरीजों की सुविधा पर लेटलतीफी

सवाई मानसिंह अस्पताल में 8 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे बहुमंजिला कॉटेज प्रोजेक्ट का करीब 54 करोड़ रुपए का बजट लेटलतीफी के कारण लैप्स हो गया।

अभी तक कागजों से ही बाहर नहीं निकल पाए इस प्रोजेक्ट को 9 साल पहले तत्कालीन अधीक्षक डॉ. नरपतसिंह शेखावत ने बनाया था। उसके बाद से अब तक जितने भी अधीक्षक आए उनमें से कोई भी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करा पाया। इसमें करीब 13-14 करोड़ की राशि दानदाताओं को देनी थी बाकी राशि राज्य सरकार वहन करने वाली थी। अब दुबारा राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद नए सिरे से प्रोजेक्ट बनेगा।

(रा.प., 18.05.17)

किसान बेहाल.. कंपनियां मालामाल

देश के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन कृषि सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की कमाई बढ़ती जा रही है। कंपनियों के स्टॉक्स बीते एक साल में 16 से 76 फीसदी तक बढ़े हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो पूरी तरह किसानों पर ही निर्भर हैं और वे किसानों के दम पर करोड़ों रुपए कमा रही हैं।

खाद का उत्पादन करने वाली कंपनियां, बीज और फसलों की सुरक्षा के उपाय बताने वाली कंपनियां, फल व सब्जी के बीज तैयार करने वाली जैसी कई कंपनियों की आय में काफी वृद्धि हुई है जबकि देश के 59 फीसदी किसान अपनी फसल को कम दामों में बेचने को विवश हैं। *(रा.प., 12.06.17)*

करप्शन के गुरूओं ने लगाई चपत

राजस्थान विश्वविद्यालय के फाइव ईयर लॉ कॉलेज में 21 प्रोफेसरों ने गैस्ट फैकल्टी बनकर 1.42 करोड़ रुपए उठाकर राजस्व को चपत लगा दी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में सामने आया कि प्रोफेसरों ने 2011 से 2013 तक फाइव ईयर लॉ कॉलेज में ग्रीष्मावकाश के दौरान मई, जून व जुलाई माह में कागजों में क्लास लेना दिखा कर लाखों रुपए उठा लिए। जबकि इन तीनों माह में कभी छात्र-छात्राएं कॉलेज में ही नहीं आए थे।

प्रोफेसरों ने जिस दिन कॉलेज में छुट्टी रहती थी, उस दिन भी कागजों में क्लास लेना बता दिया। पेपर लीक मामले के बाद सेल्फ फाइनेंस कोर्स में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया तब इसका खुलासा हुआ। अब प्रोफेसरों में हड़कंप मचा है।

(दै.भा., 23.05.17)

सांसद नहीं बदल पाए गांवों के हालात

सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रधानमंत्री एवं जन दबाव के चलते गांवों को गोद तो ले रहे हैं, लेकिन उन गांवों में हालात नहीं बदल रहे हैं। जबकि ग्रामीण विकास की इस महत्वाकांक्षी योजना की निगरानी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पास है। इसके अलावा राज्यों में मुख्य सचिवों को भी इन गांवों की प्रगति से जोड़ कर रखा गया है।

पिछले दिनों ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक में यह तथ्य उजागर हुआ है। इसके मुताबिक कई सांसदों व मंत्रियों ने पहले चरण में गोद लिए गांवों के विकास के लिए अभी तक पूरा बजट मुहैया नहीं कराया है जबकि तीसरा चरण चल रहा है लेकिन कई सांसद गांव गोद लेने से ही कन्नी काट रहे हैं। *(रा.प., 14.06.17)*

तेज हो बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई–मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ 'ऑपरेशन क्लीन मनी' की समीक्षा बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से कहा है कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए।

उन्होंने कहा कि ई–असेसमेंट व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए ताकि मानवीय दखल कम से कम हो और असेसमेंट कंप्यूटराइज्ड तरीके से लागू हो। गौरतलब है कि नोटबन्दी के फैसले के बाद सरकार ने कालेधन पर चोट करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू की है। सरकार ने बेनामी संपत्तियों और महंगी प्रॉपर्टी पर खास नजर रखते हुए जांच शुरू की।

कॉमर्शियल फ्लैटों, दुकानों की जांच काले धन के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई के तहत देश में सभी प्रमुख शहरों के हाईवे के पास की जमीनों की जांच शुरू की गई है। इसके साथ ही देश के प्रमुख शहरों के वीआईपी इलाकों में मौजूद जायदादों की जांच भी की जा रही है।

(दै.न., 03.05.17)

स्विस बैंक देगा कालाधन का ब्यौरा

स्विस बैंकों में कालाधन रखने वाले भारतीयों के बैंक खातों का ब्यौरा सरकार तक पहुंचने की राह आसान हुई है। स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ अपने यहां संबंधित देश के लोगों के वित्तीय खातों, संदिग्ध कालेधन से संबंधित सूचनाओं के आदान–प्रदान की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है।

अब इन देशों को गोपनीयता और सूचना की सुरक्षा के कड़े नियमों की अनुपालना करनी होगी। टैक्स संबंधी सूचनाओं के स्वतः आदान–प्रदान पर वैश्विक संधि को मंजूरी के प्रस्ताव पर स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद (मंत्रिमंडल) की मुहर लग गई है।

(न.नु.एवं दै.भा., 17.06.17)

सूचना देने पर मिलेगा सम्मान

ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों के लिए बनाए आवासों में भ्रष्टाचार का खेल करने वाले अफसरों पर शिकंजा कसने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने मुखबिरों का सहारा लेने का निर्णय लिया है।

विभाग की वरियता सूची में शामिल लाभार्थियों की लिस्ट स्थानीय अखबारों में प्रकाशित होगी। इस लिस्ट में से कोई भी नागरिक अपात्र लाभार्थियों के नाम की सूचना विभाग या जिला कलेक्टर को दे सकता है।

जांच के बाद यदि सूचना सही पाई गई तो सूचना देने वाले को जिला कलेक्टर के माध्यम से व्यक्तिगत यथोचित सम्मान दिया जाएगा और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। *(दै.न., 14.04.17)*

कालेधन पर किया बड़ा वार

नोटबंदी के दौरान पैसों के अवैध लेन–देन में लिप्त रहने वाली 300 कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 16 राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में इन कंपनियों के खिलाफ नवंबर और दिसंबर 2016 के बीच गलत तरीके से पैसों के लेन–देन का पता चला था। तभी से ये सरकार के रडार पर थीं। इनमें दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, बेंगलुरू, भुवनेश्वर और कोलकाता जैसे शहरों की कुछ बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं।

इन कंपनियों के खिलाफ धन शोधन निरोधक कानून और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की गई है। निदेशालय ने इस तरह की कई कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। आरोप है कि नोटबंदी के दौरान ऐसी कई कंपनियों ने करीब 3900 करोड़ रुपए के अवैध लेन–देन किए। *(दै.न., 02.04.17)*

भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होगी जांच

सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अब जांच छह महीने में पूरी करनी होगी। केन्द्र सरकार ने पुराने नियम में बदलाव करते हुए जांच की समय सीमा तय कर दी है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय लोक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 में संशोधन किया है। साथ ही जांच के महत्वपूर्ण चरणों और जांच प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा तय करने का फैसला लिया है। इससे पहले जांच पूरी करने की कोई समय सीमा नहीं थी। नियमों में बदलाव के बाद आईपीएस, आईएएस और भारतीय वन सेवा और कुछ अन्य श्रेणियों के अधिकारियों को छोड़कर सभी श्रेणी के कर्मचारियों से जुड़े ऐसे मामलों की जांच छह महीने में करनी होगी। *(रा.प. एवं दै.न., 06.06.17)*

भ्रष्टाचार देश के विकास में बाधक

राजस्थान के लोकायुक्त एस.एस. कोठारी ने कहा है कि भ्रष्टाचार व पद का दुरुपयोग देश के विकास मे सबसे बड़ी बाधा है। इसे जड़ से खत्म करना ही लोकायुक्त संस्था का मूल उद्देश्य है। लोगों को अपनी इस धारणा को मिटाना है कि व्यवस्था में रिश्वत देना अनिवार्य हो गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्रियों, अधिकारियों की अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की शिकायत लोकायुक्त को करें, ताकि प्रभावित कार्रवाई की जा सके। लोकायुक्त को निर्धारित प्रोफार्मे में या सादा कागज पर शिकायत की जा सकती है।

इसके साथ नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र भी लगाना होता है। शिकायत पर संबंधित विभाग से जवाब मांगा जाता है। शिकायत करने वाला उस पर आपत्ति भी दर्ज करा सकता है। पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करते हुए सरकार से अनुशंसा की जाती है।

(दै.न., 09.05.17)

प्रदेश में पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट

राजस्थान के 32 फीसदी लोगों ने माना है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राज्य में पुलिस विभाग में है। इस बात का खुलासा सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की हालिया सर्वे रिपोर्ट 'इंडिया करप्शन स्टडी' में किया गया है।

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 43 फीसदी लोगों का मानना है कि एक साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं 32 फीसदी लोगों का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हुआ है। प्रदेश के 25 फीसदी लोगों ने माना है कि भ्रष्टाचार न घटा है और न ही बढ़ा है। *(दै.भा., 30.05.17)*

बिजनेस में भ्रष्टाचार हुआ कम, भारत की स्थिति सुधरी

बिजनेस में भ्रष्टाचार और रिश्वत के लिहाज से भारत को इस साल 41 देशों की सूची में नौवें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2015 में भारत को छठे स्थान पर रखा गया था। इस साल भारत की स्थिति में सुधार हुआ है।

यह निष्कर्ष ईवाई यूरोप, पश्चिम एशिया, भारत और अफ्रीका (ईएमईआईए) फ्राड सर्वे 2017 नामक सर्वेक्षण में निकाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सुधार बेहतर व्यावसायिक नियमों की स्क्रूटनी और पारदर्शिता पर जोर देने से हुआ है।

भारत को यूक्रेन, साइप्रस, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका व हंगरी के बाद नौवें स्थान पर रखा गया है। ईवाई इंडिया के पार्टनर अरविंदर सिंह ने कहा है कि भारतीय कंपनियों में भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी को लेकर सोच में थोड़ा ही सही लेकिन सकारात्मक बदलाव आता दिख रहा है। भारत में नोटबंदी का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में रोकड़ी लेन-देन को हतोत्साहित कर भ्रष्टाचार और कालेधन को नियंत्रित करना था। *(रा.प., 07.04.17)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
श्रीगंगानगर	नरेश कालड़ा	गिरदावर, अनूपगढ़ तहसील, श्रीगंगानगर	30,000	रा.प., 04.04.17
राजसमंद	सुवीर कुमार तिवाड़ी	वित्त प्रबंधक, राजस्थान रोडवेज राजसमंद डिपो	5,000	रा.प., 07.04.17
भरतपुर	राजेश कुमार बंसल	महाप्रबंधक, बीएसएनएल, भरतपुर	1,00,000	रा.प., 07.04.17
अलवर	नभेन्द्र सिंह भाटी	डीपीएम, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग	1,50,000	दै.न., 12.04.17
जयपुर	महिपाल सिंह यादव	सहायक प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविधालय	40,000	दै.न. एवं न.जु., 13.04.17
टोंक	दुर्गा चौधरी	महिला पटवारी, पनवाड़ देवली, टोंक	35,000	रा.प. एवं दै.न., 13.04.17
जोधपुर	मधुसूदन शर्मा अशोक परिहार	महाप्रबंधक, सहकारी उपभोक्ता भंडार फार्मासिस्ट, दलाल	5,50,000	रा.प. एवं दै.न., 18.04.17
जयपुर	रतिराम बैंसला	राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर	10,000	रा.प.एवं दै.भा., 04.05.17
चित्तौड़गढ़	राजेन्द्र कुमार बंजारा	जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग	50,000	दै.भा. एवं रा.प., 05.05.17
अलवर	शीशराम यादव राजेश कुमार	विकास अधिकारी, बहरोड़ पंचायत समिति कनिष्ठ तकनीकी सहायक, बहरोड़ पंचायत समिति	45,000	रा.प. एवं दै.न., 11.05.17
उदयपुर	भगवान लाल जाट	ग्राम सचिव, मावली ग्राम पंचायत	25,000	दै.भा., 12.05.17
उदयपुर	देवेन्द्र कुमार मेहता	अधीक्षक, सेंट्रल एक्साइज	25,000	दै.न., 13.05.17
कोटा	संजीव गोचर	पटवारी, नगर विकासन्यास, कोटा	30,000	रा.प. एवं दै.न., 31.05.17
जयपुर	मोतीलाल मीणा	पटवारी, पटवार भवन, फागी	9,000	दै.न., 04.06.17
भरतपुर	गोपेश कुमार बृजेश	महिला थाना प्रभारी, महिला थाना, भरतपुर रीडर, महिला थाना, भरतपुर	25,000	रा.प. एवं दै.न., 06.06.17
बारां	रामलाल कुम्हार	ग्राम सचिव, पंचायत छीनोद, किशनगंज, बारां	23,000	दै.न., 07.06.17
सीकर	भैंरूबक्स मुरलीधरन	लिपिक, रीडर शाखा, खंडेला तहसील, सीकर तहसील बाबू, खंडेला तहसील, सीकर	15,000	दै.न., 15..06.17
झुंझुनूं	मुकेश सिंघल	तकनीकी सहायक, विद्युत वितरण निगम, झुंझुनूं	14,000	दै.न., 23.06.17
झालावाड़	श्याम कुमार शर्मा भैंरूलाल राठौर	मैनेजर, सेंट्रल बैंक, शाखा झालरापाटन दलाल, बैंक के बिजनेस कॉरस्पोंडेंट	10,000	दै.भा., 26.06.17

नीति आयोग: थामा राजस्थान का हाथ

राज्य के विकास में विशेष साझेदारी के अपने अभियान के तहत नीति आयोग ने उत्तरप्रदेश के बाद अब राजस्थान का रुख किया है। आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने अपने सभी शीर्ष अधिकारियों और विशेषज्ञों की पूरी टीम के साथ राज्य की मुख्यमंत्री और उनकी टीम के साथ बैठक करेंगे। आयोग राज्य के आर्थिक विकास और प्रदेश में चल रही योजनाओं की रफ्तार को तेज करने के लिए विशेष तैयारियों में जुट जाएगा।

प्रदेश में आयोग का सबसे ज्यादा जोर अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र की निराशाजनक रही हिस्सेदारी को बढ़ाना और रोजगार की कमी को दूर करने पर है। ऐसी विशेष साझेदारी के लिए नीति आयोग राज्य के अनुरोध पर ही आगे बढ़ता है। खास बात यह है कि आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया राजस्थान में ही पैदा हुए हैं। *(रा.प., 30.06.17)*

सस्ते इलाज के लिए बनेगा कानून

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकेत दिया है कि उनकी सरकार ऐसा कानून बनाएगी जिससे डॉक्टरों के लिए सस्ती जेनेरिक दवाएं ही पर्ची पर लिखना अनिवार्य होगा। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से काफी सस्ती होती है और उतनी ही कारगर होती है जितनी कि महंगी ब्रांडेड दवाएं।

उन्होंने कहा कि सरकार 15 साल के अंतराल के बाद स्वास्थ्य नीति लाई है और 700 दवाओं को सस्ता किया है। दिल के मरीजों के लगने वाले स्टेट जिसकी कीमत डेढ़ लाख रुपए थी, अब 20-22 हजार रुपए में उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा कई जरूरी दवाओं की कीमत भी कम कराने के लिए सरकार कदम उठा रही है।

(रा.प. एवं दै.न., 18.04.17)

राजस्थान को बनाएं हरा-भरा प्रदेश

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेशवासियों से राजस्थान को स्वच्छ व हरा-भरा प्रदेश बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। राजे ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखकर ही हम आने वाली पीढ़ी को सुखद व सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के पहले चरण में सभी के सहयोग से पूरे प्रदेश में 28 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए गए थे। दूसरे चरण में भी जन सहयोग से लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रदेश के सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है। *(दै.न., 05.06.17)*

मकान खरीदते वक्त 'आधार' जरूरी

फ्लेट-भूखण्ड खरीदने वालों पर अब सरकार की सीधी नजर रहेगी। बिल्डरों-खरीददारों के बीच खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया के दौरान आधार नम्बर देना अनिवार्य होगा। लीज डीड में इसका इंद्राज किया जाएगा।

रेरा के अधिसूचित नियमों के तहत लीज डीड एग्रीमेंट का फार्म भी जारी किया गया है। जिसमें आधार नम्बर का कॉलम अंकित है। सूत्रों के अनुसार केन्द्र सरकार ने इसे लेकर गंभीरता जताई थी। इसलिए राज्य सरकार ने इसे जोड़ा है। इससे सरकार को पता चल सकेगा कि किसके पास कितने आवास है और कौन आशियाने के लिए तरस रहा है।

रेरा के तहत सभी काम ऑनलाइन होंगे। इसी के जरिए बिल्डरों का रजिस्ट्रेशन, निर्माण स्वीकृति, नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया से लेकर जनता की शिकायत और निस्तारण भी वेबसाइट के जरिए होगा। *(रा.प., 02.05.17)*

अन्नपूर्णा रसोई योजना को बढ़ावा

वसुंधरा सरकार के तीन साल पूरे होने पर जयपुर सहित 12 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत इन शहरों में 80 वैनों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को पांच रुपए में नाश्ता व 8 रुपए में भरपेट खाना खिलाया जा रहा है।

योजना के सार्थक परिणामों को देखते हुए अब प्रदेश की सभी 190 स्थानीय निकायों में इस योजना को शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार योजना के संचालन में अब दानदाताओं से भी वित्तीय सहयोग ले रही है, ताकि जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्यप्रद व पोषणयुक्त भरपेट खाना उपलब्ध कराया जा सके। *(दै.न., 08.04.17)*

अव्वल छात्राएं होंगी पुरस्कृत

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 एवं 12 की परीक्षाओं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को सत्र 2017-18 से पद्माक्षी पुरस्कार प्रदान करेगी।

शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि आठवीं बोर्ड परीक्षा के लिए 40 हजार रुपए, दसवीं के लिए 75 हजार रुपए और 12वीं के लिए एक लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को न्यूनतम 60 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा। *(रा.प.,13.06.17)*

गरीबों को समय पर मिले कानूनी मदद: खेहर

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर का मानना है कि समय पर कानूनी मदद नहीं मिलने पर गरीबों का न्याय प्रक्रिया के प्रति विश्वास खत्म होता है। यही नहीं, गरीबों और अशिक्षितों को वक्त पर न्याय नहीं मिलने से कानूनी प्रक्रिया भी प्रभावित होती है।

पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी)की बैठक का उद्घाटन करते हुए जस्टिस खेहर ने कहा कि गरीबों की मदद करना बेहद जरूरी है। इस संबंध में प्रभावी योजना बनाने का समय आ गया है। वॉलंटियर्स को इसके लिए कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

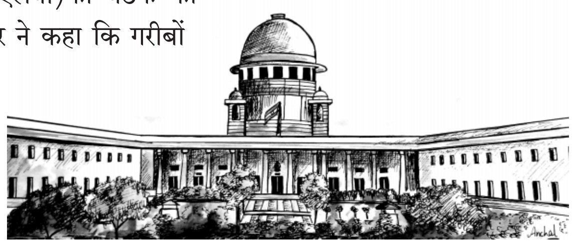

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर उस गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाना है, जो न्याय से वंचित रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय तेजी से बदल रहा है। ऐसे में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी को अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

(रा.प., 30.04.17)

सबसे सस्ती बिजली देगा भड़ला सोलर पार्क

प्रदेश के बाप क्षेत्र के भड़ला गांव में 10 हजार एकड़ में स्थापित एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में देशी-विदेशी कंपनियों के सोलर प्लांट स्थापित होने से बिजली उत्पादन के सपने अब साकार होने लगे हैं।

भड़ला सोलर पार्क के लिए हाल ही नई दिल्ली में हुई बिड में मात्र 2.44 रुपए प्रति यूनिट बिजली उत्पादन का पीपीए (पॉवर परचेज एग्रीमेंट) हुआ है, जो कोयले से उत्पादित बिजली की औसत दर करीब 3.20 रुपए प्रति यूनिट से काफी सस्ती दर है। महिन्द्रा सोलर के असिस्टेंट मैनेजर जितेन्द्र सोनी ने बताया कि यहां टैरिफ रेट 14-15 रुपए प्रति यूनिट से घटकर अब 2.44 रुपए प्रति यूनिट पर पीपीए हुआ है। *(रा.प., 25.05.17)*

अब चित्तौड़गढ़ में सोलर क्रांति

सौर ऊर्जा का उपयोग और उसे बढ़ावा देने को चित्तौड़गढ़ एवं डूंगरपुर जिलों में चल रहा नवाचार सिविल सर्विस दिवस पर प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए के लिए चयनित हुआ।

युवा आईएएस इंद्रजीत सिंह ने पहले डूंगरपुर और वर्तमान में चित्तौड़गढ़ कलेक्टर रहते हुए यह नवाचार लागू किया है। जिसके तहत अशिक्षित महिलाओं को सोलर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी गई और सोलर सिस्टम में खराबी ठीक करने वाले सूर्यमित्रा तैयार किए गए। इसकी शुरुआत उन्होंने डूंगरपुर से की थी। फलस्वरूप यह सर्वश्रेष्ठ नवाचार अवार्ड डूंगरपुर के मौजूदा कलेक्टर सुरेन्द्र कुमार सोलंकी ने प्राप्त किया।

चितौड़गढ़ पोस्टिंग के बाद इस नवाचार को इंद्रजीत सिंह ने चितौड़गढ़ में भी तेजी से लागू किया है। महिलाओं को सोलर लैंप निर्माण का प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जा रहा है। सोलर क्रांति के तीसरे चरण में चित्तौड़गढ़ में सोलर मॉड्यूल मैन्युफेक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी है। *(दै.भा., 22.04.17, 12.05.17)*

छिपाया जाता है बिजली चोरी का सच

बिजली की छीजत के लिए चोरी को जिम्मेदार बताने वाली राज्य सरकारें जनता से असलियत को छिपा रही है। असल में छीजत में बड़ा हिस्सा चोरी का नहीं बल्कि विद्युत वितरण तंत्र का है। ऊर्जा पर काम करने वाली संस्था टेरी द्वारा किए गए एक अध्ययन की रिपोर्ट में यह सच सामने आया है।

भारत में तंत्र का डिजाइन इस तरह का है कि उत्पादन गृह से उपभोक्ता के घर अथवा फैक्ट्री तक आते-आते बिजली का बड़ा हिस्सा 11 केवी की पुरानी तकनीक वाले फीडर, ट्रांसफार्मर तथा इंसूलेटर के साथ ही एलटी लाइन खा जाती है। तंत्र की खामियों का ही नतीजा है कि जापान और जर्मनी में जहां मात्र तीन फीसदी छीजत है वहीं भारत में यह आंकड़ा 25 फीसदी से भी ऊपर है। *(रा.प., 09.06.17)*

डिस्कॉम ने घटाया सुपरविजन चार्ज

नए बिजली कनेक्शन से लेकर अन्य दूसरे फील्ड वर्क के एवज में लिए जाने वाले भारी भरकम सुपरविजन चार्ज को जयपुर डिस्कॉम ने कम कर दिया है। अब उपभोक्ताओं के जॉब वर्क के दौरान बतौर सुपरविजन चार्ज कुल लागत के 15 प्रतिशत की बजाय केवल पांच प्रतिशत भुगतान करना होगा।

नई कॉलोनी या बल्क कनेक्शन में ही उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गई है कि वे अपने स्तर पर विद्युतिकरण, लाइन शिफ्टिंग, अंडरग्राउंड केबलिंग जैसे काम करवा ले। इसके लिए डिस्कॉम पूरा ऐस्टीमेट तैयार करवाता है और सुपरविजन चार्ज के तौर पर कुल लागत का 15 फीसदी राशि वसूल करता है। अब ऐसी स्थिति में डिस्कॉम सिर्फ 5 फीसदी चार्ज ही वसूलेगा। *(दै.भा., 17.06.17)*

बिजली सेवा में कमी, मिलेगा हर्जाना

बिजली की सेवा समय पर नहीं मिलने पर उपभोक्ता अब हर्जाना ले सकेंगे। यह हर्जाना काम में देरी करने वाले अधिकारी से वसूला जाएगा। इसके लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने विद्युत सेवा दोष क्षतिपूर्ति प्रकोष्ठ का गठन किया है।

निगम के प्रबंध निदेशक आर.जी.गुप्ता की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर प्रभावित उपभोक्ता आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए सेवा की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर उपखंड कार्यालय में आवेदन कर सकता है। *(रा.प., 21.06.17)*

किसानों को भाई सौर ऊर्जा से खेती

प्रदेश में बहुत से किसान खेतों में सिंचाई के लिए अब बिजली की बजाय सौर ऊर्जा का उपयोग करने लगे हैं। इस साल प्रदेश के साढ़े नौ हजार किसानों ने अपने खेत में सोलर पंप सिस्टम लगाकर भारी बिजली बिल से छुटकारा पाया है। इससे किसानों को बिजली गुल होने और दरें बढ़ने की चिंता से भी राहत मिली है।

किसानों को सोलर पंप का उपयोग करने पर 60 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। बिजली कनेक्शन सरेंडर करके सोलर पंप खरीदने वाले किसानों को 75 फीसदी अनुदान दिया जाता है। *(रा.प., 02.04.17)*

नीति आयोग की ऊर्जा विस्तार योजना

नीति आयोग ने 2017-18 की अवधि के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में एक विशेष कार्य योजना की घोषणा की है। इसी सन्दर्भ में अनेक लक्ष्य और नीतिगत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस कार्य योजना में ऊर्जा कुशलता को खास महत्व दिया गया है। आयोग ने सभी प्रमुख ऊर्जा क्षेत्रों को इस कार्ययोजना में शामिल किया है।

आयोग नें वर्तमान कमजोर प्लान्ट लोडफेक्टर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसा कमजोर मांग के कारण हो रहा है। आयोग ने 2019-20 तक क्षमता विस्तार को लेकर सावधानी बरतने की बात भी कही है। ऊर्जा कुशलता की आवश्यकता बताते हुए आयोग ने कहा है कि प्रदूषण संबंधित मानकों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। *(न.नु., 03.05.17)*

पेयजल मानकों में आया सुधार

विश्व जल परिषद के अध्यक्ष बेनेदितो ब्रागा ने बताया कि परिषद द्वारा भारत सहित दुनिया के प्रमुख हिस्सों में पानी के प्रति जागरूकता को लेकर एक सर्वेक्षण किया गया है। जिसके अनुसार भारत में पिछले पांच सालों के दौरान पेयजल मानकों में काफी सुधार आया है। यह सर्वेक्षण विश्व जल मंच के आयोजन से पहले किया गया है जो कि मार्च 2018 में ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में होने जा रहा है।

सर्वेक्षण के अनुसार एक तिहाई से अधिक भारतीयों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को पाने के लिए अभी काफी कुछ करना बाकी है। इस लक्ष्य के मुताबिक वर्ष 2030 तक सभी को पानी और स्वच्छता सुलभ होनी चाहिए। सर्वेक्षण में कहा गया है 62 प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि सुरक्षित पीने के पानी के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। ब्रागा ने भारत के स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करते हुए पीने के साफ पानी और स्वच्छता के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की है।

(न.ज्यो., 07.05.17)

गांवों को मिलेगा शुद्ध पानी

प्रदेश के फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी मुहैया करवाने के लिए अब कार्य योजना तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए फंड मंजूर कर दिया है। इससे फ्लोराइड प्रभावित गांवों और ढ़ाणियों में पेयजल समस्या का स्थाई निदान हो सकेगा। फ्लोराइड से प्रभावित 31 जिलों की करीब चालीस लाख की आबादी इससे लाभान्वित होगी।

प्रदेश में अधिकतर जगहों पर भूजल ही पीने के काम में लिया जाता है। योजना के तहत गांवों में अब नई तकनीक के जरिए लोगों को सतही जल के माध्यम से शुद्ध और मीठा पानी मिल सकेगा। प्रभावित क्षेत्रों में आरओ रिवर्स भी लगाए जाएंगे। कई क्षेत्रों में जहां पर पानी में फ्लोराइड और नाइट्रेट की मात्रा अधिक है उनमें आरओ के जरिए भी शुद्ध पानी मुहैया कराया जा रहा है।

(दै.न., 22.06.17)

विभाग ने दिए निर्देश, सहेजो पानी!

जल स्वावलंबन अभियान के बावजूद खुद सरकारी विभाग ही पानी सहेजने में रुचि नहीं दिखा रहे। इससे चिन्तित स्वायत शासन विभाग को रूफटॉप वॉटर हार्वेस्टिंग पर काम तेज करने के निर्देश देने पड़े हैं।

सरकारी इमारतों में रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अनिवार्यता के बावजूद कई निकाय कछुआ चाल चल रहे हैं। विभाग ने 1686 कार्यों में से रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग के लिए ही 1462 चिन्हित किए हैं। इनमें से 748 के कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। लेकिन काम पूरे होने का आंकड़ा कम है।

(रा.प., 02.04.17)

महंगा हुआ पानी, नई दरें लागू

प्रदेशभर में एक अप्रेल से पानी का बिल 10 फीसदी महंगा हो गया। जलदाय विभाग ने बिना टैरिफ रिव्यू किए डेढ़ साल पुराने आदेश के तहत यह बढ़ोतरी की है। पिछले डेढ़ साल में ही पानी का बिल 68 फीसदी तक महंगा हो गया। जबकि हर शहर व प्रदेश में रिव्यू करने के बाद पानी की टैरिफ बढ़ती है।

टैरिफ बढ़ाने से पहले प्रोजेक्ट के खर्चे व अन्य शहरों के पेयजल दरों की तुलना की जाती है। इसके बाद ही बिल बढ़ाने का फैसला होता है। जबकि पिछले एक साल में शहरों की पेयजल सप्लाई में सुधार के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं हुआ है। अब विभाग के इंजीनियरों ने तो हर साल 10 फीसदी रेट बढ़ाने का नियम ही बना दिया है।

(रा.प. एवं दै.भा., 02.04.17)

बावड़ियों के पानी से बागवानी

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति में करीब 57 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि अभियान के सैकंड फेस में बावड़ियों को पुनर्जीवित करने के काम हाथ में लिए गए हैं। बावड़ियों की सफाई के बाद उसके पानी को बागवानी जैसे कार्यों में काम में लिया जाए।

उन्होंने जल संग्रहण ढांचों के निर्माण कार्य को गति देने और जहां वित्तीय स्वीकृति नहीं हो पाई है वहां तुरंत स्वीकृति जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। *(दै.न., 04.06.17)*

प्रदेश में बनेगी विस्तृत जल नीति

राजस्थान हाईकोर्ट में प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए विस्तृत जल नीति बनाई जा रही है। सरकार की ओर से नीति पेश करने के लिए तीन माह का समय मांगा गया।

इस पर अदालत ने कहा कि पेयजल काफी गंभीर मामला है, सरकार इसे हल्के में न लेकर बार-बार तारीख न ले। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश महेश पारीक की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। *(दै.न., 25.04.17)*

पेयजल स्त्रोतों की होगी निगरानी

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी पेयजल स्त्रोतों की राजधारा सर्वे मोबाइल एप के जरिए जियो टैगिंग की जाएगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसका प्रारूप तय कर जलदाय विभाग को दे दिया है। जलदाय विभाग ने अब सभी अभियंताओं को इस मॉनिटरिंग को लेकर निर्देशित किया है।

जल स्वावलंबन अभियान के तहत जल स्त्रोतों को विकसित करने की पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन जानकारी मुहैया हो रही है। इसी तर्ज पर अब जलदाय विभाग के सभी जल स्त्रोतों के लिए राजधारा सर्वे मोबाइल एप तैयार किया गया है। इससे पता लगेगा कि जल स्त्रोतों की क्या स्थिति है। *(दै.न., 17.06.17)*

गांव ने कायम की अनूठी मिसाल

प्रदेश के राजसमंद जिले के पीपलान्त्री गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 फलदार पेड़ लगाए जाते हैं। इन पेड़ों की सुरक्षा का बीड़ा भी गांव वाले ही मिलकर उठाते हैं। दीमक आदि से बचाव के लिए वे पेड़ों के चारों ओर एलोवेरा के पौधे भी लगाते हैं।

इसके अलावा गांव के निवासी मिलकर 21 हजार रुपए व बच्ची के माता-पिता 10 हजार रुपए कुल 31 हजार रुपए की बिटिया के लिए बैंक में 20 साल के लिए एफ.डी. भी करवाते हैं। बिटिया के माता-पिता इस बात का लिखित में हलफनामा भी देते हैं कि वे अपनी बेटी को उचित शिक्षा दिलवाएंगे और कानूनी उम्र होने पर ही उसका विवाह करेंगे। गांव में लगाए गए पेड़ और एलोवेरा के पौधे गांव के निवासियों के लिए उनकी जीविका का साधन बन गए हैं। देश के अन्य गांवों के लिए यह मिसाल प्रेरणा दायक है।

राष्ट्रीय महिला नीति की तैयारी...

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में बने मंत्री समूह ने महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है। इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जा सकता है। अगर नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई तो सरकार बुजुर्ग और खासकर विधवा महिलाओं के जीवनयापन में मदद को प्राथमिकता देगी।

महिला नीति में महिलाओं के लिए आधार से जुड़े हेल्थ कार्ड बनाकर मुफ्त स्वास्थ्य जांच, आयकर में राहत, गर्भवती महिलाओं के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा, मुफ्त कानूनी सहायता देने जैसी कई सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं।

(रा.प., 08.05.17)

अब भी घरों में हो रही डिलेवरी

प्रदेश में अभी भी ऐसे गांव-ढ़ाणियां हैं, जहां गर्भवती महिलाएं डिलेवरी के लिए अस्पताल नहीं आती हैं। कैग की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पिछले पांच साल में औसतन एक लाख महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल का रुख नहीं कर रहीं।

चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पांच साल में 67 लाख 3 हजार 450 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। इनमें से 5 लाख 8 हजार 23 महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल नहीं आईं। उनके प्रसव घरों में ही अप्रशिक्षित दाइयों व रिश्तेदारों ने कराए। यह चिकित्सा विभाग के तंत्र पर सवाल खड़ा करता है। *(दै.न., 17.04.-17)*

कम हुए, लेकिन हो रहे हैं बाल विवाह

प्रदेश में आज भी बाल विवाह जैसी कुरीति सिर उठाए खड़ी है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच 1.2 करोड़ बच्चों की नाबालिक अवस्था में शादी हुई । इनमें से 29 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका विवाह 11 से 14 वर्ष की उम्र में हुआ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हाल ही जारी रिपोर्ट में यह हकीकत सामने आई है। बाल आयोग ने यंग लाइव इंडिया नामक एक संस्था के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि रिपोर्ट जनगणना 2011 व राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़ों पर आधारित है।

रिपोर्ट के अनुसार 11 से 14 वर्ष के 29 लाख बच्चों में 11 लाख लड़के व 13 लाख लड़कियां शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में आगे के सालों में लगातार बाल विवाह के आंकड़ों में गिरावट आ रही है।

(रा.प., 04.06.17)

जहां मां शिक्षित, वहां बच्चे भी सुरक्षित

मां शिक्षित है तो वह पूरे परिवार की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाती है। इस तथ्य को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 की रिपोर्ट साबित कर रही है। सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में उन क्षेत्रों में बच्चों के टीकाकरण की दर ज्यादा है, जहां महिलाएं पढ़ी-लिखी हैं।

सर्वेक्षण के दौरान प्रदेश के कई जिलों में महिलाओं की साक्षरता दर और बच्चों का टीकाकरण प्रतिशत लगभग बराबर पाया गया। सर्वेक्षण से सामने आया कि जहां साक्षरता दर ज्यादा है, वहां बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की दर भी ज्यादा है। गौरतलब है कि बच्चों का पूर्ण टीकाकरण उन्हें भविष्य में बीमारियों से सुरक्षा देता है। साथ ही स्वास्थ्य, लंबाई, वजन जैसे पैमानों पर बेहतरी की ओर ले जाता है।

(रा.प., 30.04.17)

सीखे स्वावलंबन का पाठः राजे

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धौलपुर में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली महिलाओं के समूह से मुलाकात की। कृषि सखी, पशु सखी, जन सखी के तौर पर लोगों को खेतीबाड़ी, पशुपालन, डेयरी आदि की आधुनिक तकनीकों का उपयोग सिखाने वाली इन महिलाओं के हौसले, लगन और आत्मविश्वास की मुख्यमंत्री ने जमकर सराहना की है।

उन्होंने कहा कि धौलपुर की इन महिलाओं ने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया, उससे इस जिले के ग्रामीण जन-जीवन में एक आशा का संचार हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन महिलाओं को पास के अन्य जिलों में प्रशिक्षण देने के लिए भेजा जाए, ताकि वहां भी इस तरह का कायाकल्प हो सके। *(दै.न., 20.05.17)*

फैमिली प्लानिंग महिलाओं के भरोसे

राजस्थान में परिवार को छोटा रखने का जिम्मा महिलाओं के भरोसे पर है। नसबन्दी कराने में आज भी पुरुष परहेज कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग के भरसक प्रयासों के बावजूद नतीजा सिफर है। केवल कुछ ही पुरुष नसबन्दी कराकर फैमिली प्लानिंग अपना रहे हैं। जबकि महिलाओं की संख्या हर साल लाखों में है।

कैग की रिपोर्ट में पांच सालों के आंकड़ों पर नजर डाले तो पता चलता है कि महिलाओं में इसके प्रति जागरूकता है। राजस्थान में 2011-12 से लेकर 2015-16 के बीच चिकित्सा विभाग के अनुसार करीब 15 लाख 2 हजार महिलाओं ने नसबन्दी करा कर परिवार सीमित करने की जिम्मेदारी ली। जबकि केवल 23 हजार पुरुषों ने नसबन्दी करा कर इसकी चिंता की। *(दै.न., 01.05.17)*

वित्तीय सेवाएं

बैंक खाते के लिए आधार व पैन जरूरी

सरकार ने बैंक खाताधारकों तथा नया खाता खुलवाने वालों के लिए आधार और पैन नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा एक जून को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि नया खाता खुलवाने के लिए छह महीने के भीतर तथा पुराने खाताधारकों को इस साल 31 दिसंबर तक बैंक में अपना पैन और आधार नंबर देना होगा अन्यथा उनके खाते से लेन-देन पर रोक लगा दी जाएगी।

हालांकि इसमें लघु खाताधारकों व जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के नागरिकों को इससे छूट दी गई है। अधिसूचना के जरिए धन शोधन निरोधक (रिकॉर्डों का रखरखाव) नियम 2005 में बदलाव कर यह व्यवस्था की गई है।

(दै.न., 17.06.17)

दूरसंचार सेवाएं

नापा जा सकेगा मोबाइल रेडिएशन का स्तर

संचार मंत्रालय ने तरंग वेबपोर्टल जारी कर दावा किया है कि देश का हर नागरिक ऑनलाइन अपने इलाके के साथ ही देश में लगे हुए किसी भी टावर का रेडिएशन स्तर नाप सकता है।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर के हरीश चंद्र तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए माना था कि मोबाइल टावर रेडिएशन से कैंसर होता है। कोर्ट ने टावर हटवाने का आदेश भी दिया था, लेकिन संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि देश में एक अजीब तरह की भ्रांति फैली हुई है कि मोबाइल टावर रेडिएशन से कैंसर होता है।

सिन्हा ने कहा कि विश्वभर में पिछले तीस सालों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 25 हजार से भी अधिक अध्ययनों का हवाला देते हुए कई बार कहा है कि टावरों से कम स्तर के विद्युत चुम्बकीय फील्ड के उत्सर्जन से मानव स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव नहीं होता। इसके बावजूद देश में नागरिक इस भ्रांति से मुक्त नहीं हो पाए।

(रा.प., 03.05.17)

सड़क सुरक्षा

हर साल होती है 3500 बाइक सवारों की मौत

प्रदेश में हर साल 10 हजार लोगों की सड़क हादसों से होने वाली मौतों में 35 फीसदी यानी 3500 से ज्यादा बाइक सवार होते हैं। पिछले तीन सालों और इस साल की पहली तिमाही में हुए सड़क हादसों के विश्लेषण में यह दुःखद आंकड़ा निकल कर सामने आया है।

इस साल मार्च तक प्रदेश में 2564 लोगों की मौत सड़क हादसों में हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, हनुमानगढ़, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़ और पाली जिलों में हुई है। मृतकों की संख्या के लिहाज से सबसे अधिक 83 फीसदी की बढ़ोतरी हनुमानगढ़ और दूसरे नंबर पर जयपुर उत्तर में 71 फीसदी तक बढ़ी है।

गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया खुद मानते हैं कि यह काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कोशिशें बहुत हो रही हैं लेकिन नतीजे संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। प्रदेश में 35 फीसदी मौतें बाइक सवारों की हो रही है। हैलमेट नहीं पहना है, न ही मोबाइल पर बात करनी छोड़ी, सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी ही नहीं है अथवा पालना नहीं की जा रही जिससे यह हादसे बढ़ते हैं। हम जल्द ही स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा का पाठ शामिल करेंगे, ताकि स्कूल से ही बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी मिल सके।

(दै.भा., 17.05.17)

जन स्वास्थ्य

हेल्थ चैकअप कराएगी सरकार

सरकार यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम के जरिए देश के 30 साल से अधिक उम्र के 50 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच करने जा रही है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियां भारत में होने वाली 60 फीसदी मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत सरकार यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत 100 जिलों में करने जा रही है इसके तहत हाईपरटेंशन, मधुमेह, बच्चेदानी का कैंसर, स्तन और मुंह के कैंसर की जांच की जाएगी।

अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाएगी और 30 साल से अधिक आयु के सभी लोगों की मुफ्त जांच करेगी। जांच में यदि यह सामने आता है कि मरीज की हालत गंभीर है तो यह टीम मरीज को पहले प्राईमरी हेल्थ सेंटर और फिर जरूरत पड़ी तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंचाएगी। अभियान के तहत मरीजों की एक हेल्थ डायरी भी बनेगी।

(दै.भा., 18.05.17)

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में 300 से अधिक नए पैकेज शामिल करने को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने अधिकारियों को इस लोकप्रिय फ्लेगशिप योजना को और अधिक बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। योजना में नेफ्रोलॉजी, गेस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी सहित अन्य स्पेशियलिटी उपचार के पैकेज जोड़ने का प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजना दूसरे प्रदेशों की बीमा योजनाओं के मुकाबले सस्ती है। साथ ही उन्होंने विभिन्न बीमा पैकेजों का तुलनात्मक अध्ययन कर उन्हें और अधिक सस्ता और बेहतर बनाने का सुझाव दिया, ताकि कम से कम लागत में मरीजों को बेहतरीन उपचार सुलभ कराया जा सके।

(दै.न., 17.06.17)

उपभोक्ता फैसले

बिजली बिल में ज्यादा राशि वसूलना गलत

जयपुर स्थित गोपालपुरा बाईपास निवासी कृपा देवी ने उपभोक्ता मंच द्वितीय में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खिलाफ परिवाद दायर करते हुए बताया कि विद्युत निगम ने उनके घर में चलने वाली आटा चक्की को एक कनेक्शन दिया था। राशि बकाया होने पर 2007 में इस कनेक्शन को काट दिया गया। इसके बाद विद्युत निगम ने उसे दिसंबर 2014 के लिए 34,203 रुपए का बिजली बिल भेजा। जबकि इस माह में सिर्फ 272 यूनिट बिजली ही उपभोग ली गई थी। उसने इसकी शिकायत भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में बताया गया कि उनके घर में सात साल पहले लगी आटा चक्की के बिल की बकाया को इस बिल में जोड़ा गया है।

मामले की सुनवाई पर मंच ने माना कि कृपा देवी के नाम से कनेक्शन में किसी तरह का कोई बकाया नहीं था। साथ ही उनके घर पर लगी चक्की का कनेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम था। नियमानुसार कोई भी बकाया राशि सिर्फ दो साल के अन्दर ही वसूली जा सकती है। जबकि विद्युत निगम ने सात साल बाद यह राशि कृपा देवी के बिल में जोड़कर भेजी, जो गलत है। उपभोक्ता मंच ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आदेश दिया कि वह कृपा देवी से सिर्फ उपभोग की गई बिजली का ही बिल वसूल कर सकता है। बाकी राशि उनसे प्राप्त करने का उसे कोई अधिकार नहीं है।

(डे.न्यू., 13.05.17)

जीवन की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी और समाज का दायित्वः इन्द्रजीत सिंह

प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें गंभीर चिंता का विषय है। जीवन अमूल्य है जिसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी और समाज का दायित्व है। उक्त विचार 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा चित्तौड़गढ़ स्थित होटल पद्मिनी में आयोजित संभाग स्तरीय पैरवी बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन एवं सड़क सुरक्षा की नई तकनीकों का उपयोग कर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

प्रारम्भिक संबोधन में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि भारतीय सड़कों पर हर घंटे 57 दुर्घटनाएं होती है जिनमें 15 लोग अपनी जिन्दगी खो देते हैं। पूरे विश्व में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 10 प्रतिशत दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। तकनीकी सत्र के मॉडरेटर 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना की उपस्थिति में आधार फाउंडेशन के सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ एन.एल. चौधरी ने भारत के सड़क सुरक्षा परिदृश्य को प्रस्तुत किया। मोबीक्वील एप्स नई दिल्ली के निदेशक विभोर गुप्ता ने हमसफर एप्स तथा 'कट्स' के मधुसूदन शर्मा ने मोटर वाहन बिल, 2016 के बारे में चर्चा की।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से किया सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तब से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है।

इस बार वर्ष 2016 के लिए यह पुरस्कार 'कट्स' द्वारा आयोजित 'प्रो–ऑर्गेनिक–द्वितीय' परियोजना के औपचारिक शुभारम्भ समारोह के दौरान मुख्य अतिथि प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, राजस्थान द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने दैनिक भास्कर के पत्रकार चैतन्य कुमार मीणा को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया।

चैतन्य कुमार मीणा सीकर जिले के अजीतगढ़ के निवासी हैं। उन्होंने वर्ष 2016 के लिए चयनित विषय 'जल स्वावलंबन अभियान' विषय पर प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर में अनेक रोचक एवं तार्किक स्टोरियां प्रकाशित कर आमजन में जागरूकता लाने एवं जनचेतना जागृत करने का काम किया है।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, डे.न्यू.: डेलीन्यूज

पाँचवा–स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी–217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई–मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।